

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 15, 2018/ आश्विन 23, 1940

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 630

No. 198]

DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ ASVINA 23, 1940

[N.C.T.D. No. 630

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2018

सं. ६०(५९)डीएसडब्ल्यू/डीडीडब्ल्यू डब्ल्यू/पार्ट- 3/-27019-034.—दिल्ली महिला आयोग अधिनियम १९९४ (दिल्ली अधिनियम १९९४ की संख्या ८) की धारा १७ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग(अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय, भत्तें एवं सेवाओं की शर्तें एवं अन्य प्रावधान) नियमावली २००० को निम्नानुसार संशोधित करती है अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -

- 1) इन नियमों को दिल्ली महिला आयोग(अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय, भत्तें एवं सेवाओं की शर्तें एवं अन्य प्रावधान) (संशोधन) नियमावली २०१८ कहा जायेगा।
- 2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम ३ में संशोधन: - दिल्ली महिला आयोग(अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय, भत्तें एवं सेवाओं की शर्तें एवं अन्य प्रावधान (नियमावली २०००; नियम ३ में, उप-नियम (i) और (ii), निम्नलिखित उप नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i) अध्यक्ष को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त(गैर-आधिकारिक) किया जाएगा और प्रति माह २,००,००० / - (दो लाख रुपये मात्र) (समेकित) मानदेय का भुगतान बिना भत्ते के किया जाएगा। अध्यक्ष नियमानुसार दिये जाने वाले वाहन एवं मकान या मकान किराया भत्ता के भी हकदार होंगे।

(ii) अन्य सदस्यों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और ऐसे सदस्यों में से प्रत्येक को प्रति माह १,००,००० / - (समेकित) मानदेय का भुगतान बिना भत्ते के किया जाएगा। "

उक्त अधिसूचना मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन द्वारा जारी की जाती है।

जे. के. जैन, संयुक्त निदेशक,

**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT  
(WOMEN EMPOWERMENT CELL)**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 10<sup>th</sup> October, 2018

**No.F.60(59)/DSW/DDWW/Part-III/ 27019-034.**—In exercise of powers conferred by section 17 of the Delhi Commission for Women Act, 1994 (Delhi Act No.8 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Commission for Women(Honorarium and Allowances and Conditions of the Service of the Chairperson and Members and other provisions) Rules, 2000, namely:-

**1. Short Title and Commencement :-**

- (1) The rules may be called the Delhi Commission for Women(Honorarium and Allowances and Conditions of the Service of the Chairperson and Members and other provisions)(Amendment) Rules 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their notification in the Delhi Gazette.

**2. Amendment of rule 3:-** In the Delhi Commission for Women (Honorarium and Allowances and Conditions of the Service of the Chairperson and Members and other provisions) Rules 2000 ; in rule 3, the sub – rules (i) and (ii), the following sub rules shall substituted, namely:-

“(i) The Chairperson shall be appointed on full time basis (non-official) and shall be paid honorarium of Rs.200,000/- (Rs.Two lakhs only) (Consolidated) per month without allowances. The Chairperson will also be entitled to a car and house or HRA as applicable as per rules.

(ii) Other Members shall be appointed on part-time basis and each of such members shall be paid honorarium of Rs.1,00,000/- (consolidated) per month without allowances.”

This issues with the approval of Minister for Women and Child Development Govt. of NCT of Delhi.

J.K. JAIN, Jt. Director